Konkan Railway

1177. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what are the details of activities of the Konkan Railway;

(b) whether Corporate Office of this organisation has been set up in Rail Bhawan;

(c) whether Corporate Office of any other organisation under the Ministry has been set up in Rail Bhawan;

(d) if so, details thereof and if not. the reasons for allowing this organisation to remain in Rail Bhawan when acute shortage of accommodation for staff and officers is being felt in the building;

(e) whether the Corporate Office of this organisation has 90 per cent retired officials', and

(f) if so, the details thereof cadre-wise and emoluments being paid to each?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K.C. LENKA): (a) Konkan Railway Corporation Limited (KRC) is engaged in the construction of the 760 km. broad gauge Railway line from Roha to Mangalore. They arc also to operate the Railway after the line is constructed.

(b) The Registered Office of KRC is located in Rail Bhawan but the Corporate Office is in Belapur at New Bombay.

(c) No, Sir.

(d) KRCs Registered Office is located in Rail Bhawan for better coordination with the Railway Board as the Project has a very tight time schedule of completion by October, 1994.

(e) No, sir.

(f) Does not arise.

Completion of Railway Track from Roha to Dasgaon

1178. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that railway track from Roha to Dasgaon (Konkan Railway) has been completed; and

(b) if so, by when the traffic on this railway track is likely to commence?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K.C. LENKA): (a) Yes, Sir.

(b) March, 1993.

रेलवे को हुआ घाटा

1179. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर:**
श्री सत्य प्रकाश मालवीय:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान लोक लेखा समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी उस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा है कि अनियमितताओं के कारण रेलवे को 95 लाख रुपये से अधिक का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्देशों और सुझावों के बावजूद मैसर्स एन०ई०आई० को दिये गये आपूर्ति आदेशों को किस आधार पर परिवर्तित किया गया जिसके परिणामस्वरूप मंत्रालय को सीमा शुल्क के रूप में 77 लाख रुपये वापस देने पड़े हैं;

(ग) क्या उक्त विदेशी कंपनी को शेलमर बेयरिंग की सप्लाई किये जाने के मामले में अवांछनीय फायदा पहुंचाया गया है जबकि समिति ने इस संबंध में मंत्रालय को सूचित किया था;

(घ) क्या सरकार ने उक्त मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन के संबंध में लोक लेखा समिति के सुझाव की ओर ध्यान दिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका): (क) जी हां।

(ख) मैसर्स एन०ई०आई० विदेशी कम्पनी नहीं है अपितु एक भारतीय कंपनी है जो जयपुर में स्थित है, चूंकि यह एक सांविधिक दायित्व है, इसलिए सीमा शुल्क के भुगतान के रूप में उन्हें 77 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की गई है।